

(The Directive Principles of State Policy)

सर्वोपयोग ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का धर्नाकरण स्पष्ट रूप से नहीं किया है।

7. शिक्षासम्बन्ध में सरकारी जवाबदाई - पिछले 34 वर्षों का अनुभव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल कुछ शाखाओं में ही हम शिक्षा विभाग विद्यार्थी को स्थायी रूप से शिक्षा प्रदान कर प्रदान नहीं कर पाए हैं। आज हमारे पास ऐसा शिक्षा प्राप्त करने की एकमात्र व्यवस्था शिक्षा विभाग है।

तन्त्र की नीति के निर्देशक तत्वों का महत्त्व
(Importance of the D.)

(Importance of the Directive Principles of State Policy)

[illegible]

1. देश के प्रशासन के सुधारों-नीति के निर्देशक तत्व कार्य-योजना में होई हुए भी स्थिति को 'असमर्थता' है। संविधान में इनका उल्लेख तो हो चुका, अनुशासन और नीति का प्रयोग बाला है। संविधान इन्हीं देश के प्रशासन में सुधार का पहला ही है। केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का स्वायत्ततामय रहना ही देश के प्रशासन-निर्माण का तो सत्य है। इन तथ्यों को संघीयता का एक अंग माना है। ये सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। ये सत्य अनुसूच जाति, क्षेत्र तथा वर्ग समुदायों को इन सत्य का एक हिस्सा रखने के लिए संघीय धित के लिए, उसे कार्य करना चाहिए। इन दिनों ये प्रश्न का अर्थ ही प्रशासनिक है ?
2. समाजवाद के अर्थों में प्रशासनिक है ?

- [illegible]

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible]

६. भारतीय परिस्थितियों में प्रोबेट-सीज विवेकमय रूप 'अपना' साज नहीं, यदि अपराधी
निर्दोष हो तो वे उसे को संश्लेषित को प्रभावित हुए भी वे अपराधी परिस्थितियों में ही अपराधी हो
सकते हैं। उदाहरण: माया विषय, माया में पाश्चात्त्य को स्थापित, मुद्रा वस्तुओं का विकास, दुष्कृत
को बना, पिछले न के माया अनुसंधान आदि को भी अनुसंधान जैव-वैज्ञानिक को संश्लेषित, उदाहरण
और सार्वजनिक जगहों, उदाहरण के अनुसार को भी अनुसंधान जैव-वैज्ञानिक को संश्लेषित, उदाहरण
संश्लेषित, सार्वजनिक की संश्लेषित को भी अनुसंधान जैव-वैज्ञानिक को संश्लेषित, उदाहरण

1. भारत निर्देशक तन्त्रों की व्यवस्थापना के लिए एक विशेष बॉर्डर को चुनने का प्रयास कर रहा है।

के जो प्रत्यक्ष विचारित करने का प्रयास किया है। उदाहरणतः सम्पत्ति के कुछ हाथों में
 अधिकार का प्रसार और इस पर नियंत्रण रखने के लिए उसे मूल अधिकारों के अन्तर्गत से निकाल
 दिया गया है। उपर्युक्त के मुक्त-मुक्त सधनों को सार्वजनिक नियंत्रण में ले लिया गया है तथा
 निम्नलिखित रूपों के लिए अनेक शैक्षणिक और आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पिछले 54 वर्षों
 में इन सब का फलकारी द्वारा इनके अनेक फलफलों को लागू करने का सार्विक प्रयास किया
 गया है।

मूल अधिकारों के निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में अन्तर

Principles of Fundamental Rights and
 Difference between Principles of State Policy

मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर को निम्नलिखित रूप से विस्तारित
 किया जा सकता है:-

1. मूल अधिकार निर्देशक हैं। वे राज्य की शक्त को मर्यादित करते हैं तथा उसे कुछ
 बातों करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरी ओर, नीति निर्देशक तत्व सरकारालयक अपेक्षाएँ हैं। वे
 राज्य को सलाह देते हैं, सरकार को प्रगति के लिए कुछ कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं।

2. मूल अधिकार बाध्य-योग्य हैं। जब कभी कार्यपालिका आदेश या व्यवस्थापिका के
 द्वारा कानून के अन्तर्गत अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो वे न्यायालयों से संरक्षण प्राप्त कर
 सकते हैं। दूसरी ओर, नीति निर्देशक तत्व बाध्य-योग्य नहीं। यदि राज्य इनकी उल्लंघना करता है
 तो कानून न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है।

3. मूल अधिकार तत्त्व पर कानूनी बन्धन लगाने करते हैं और यदि कार्यपालिका आदेश
 या व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायालय उस माया
 तत्त्व को अंग धोकर कर सकता है जिस माया तक वे अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।
 नीति निर्देशक तत्व तब तक पर नैतिक बन्धन आरोपित करते हैं। न्यायालय किसी
 व्यवस्थापिका द्वारा या व्यवस्थापिका के कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर
 सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों के अतिक्रमण है।

4. मूल अधिकार व्यक्ति (नागरिक) के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं परन्तु
 नीति निर्देशक तत्वों का सम्बन्ध निजी अधिकारों से नहीं, इनका सम्बन्ध समाज के अधिकारों
 से है। नीति निर्देशक तत्वों में सार्वजनिक दायित्वों की प्राप्ति के लिए कानून द्वारा कार्यान्वित
 किए जा सकते हैं।

5. मूल अधिकार देश में राजनीतिक लोकतन्त्र को स्थापना करते हैं, जबकि नीति-
 निर्देशक तत्वों की विवेचिति से आर्थिक लोकतन्त्र को स्थापना होती है।

6. मूल अधिकार भारतीय संविधान में प्राथमिक दर्जा से ग्रहण किये गये हैं, जबकि नीति
 निर्देशक तत्वों को संविधान में समाप्त करने के बाद भारतीय संविधानिक परिवेश तथा

मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में क्या कोई विरोध है?

अब हम यह देखेंगे कि क्या मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में
 कोई विरोध है। इस बात के जवाबदायक अन्वेषण के लिए हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या कोई
 प्रश्न नहीं होता कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विरोध है। सार्वजनिक तौर पर यह कि
 दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। यदि संविधान का भाग तीन भारतीय संविधान के
 दर्शन को अधिष्ठाता करता है तो भाग चार हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अनेक अर्थों और इन
 अर्थों को कवित करने वाली रीतियों को अधिष्ठाता करता है। उदाहरणतः यदि भाग तीन के
 अनुच्छेद 14 से 18 "नागरिकों को समानता के अधिकारों का समर्थन" और "निर्धन के अधिकारों का
 संरक्षण" का अधिकार प्रदान करते हैं तो भाग चार के अनुच्छेद 38 और 39 उन उन
 परिस्थितियों की रचना करते हैं जिनके विद्यमान होने पर ही सामाजिक या सामाजिक
 कार्यात्मक समानता विद्यमान हो सकती है। मूलतः न्यायाधीश के द्वारा हेमदे ने लिखा है कि
 "संविधान के चौथे भाग में दिये गये उपर्युक्त तत्वों भाग में दिये गये उपर्युक्तों को पूरा
 करते हैं और वे दोनों भाग मिलकर कार्यान्वयनकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिए
 एक योजना प्रस्तुत करते हैं।"

सन् 1980 में गिरवा निगत बनाने भारत संघ के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल
 अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सम्बन्धों को पुनः स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय का मत
 है कि "नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में तालमेल और समुचित संबंधन को मूल
 विरोध है। एक को दूसरे से प्राथमिकता देना उस तालमेल में बाधा प्रस्तुत करता है। न्यायालय
 का मत है कि, "यदि नीति निर्देशक तत्वों में निर्दिष्ट अर्थों को प्रगति के लिए मान्य व्यवस्था
 को योजना चुकानी पड़ती है तो वे आत्मचार के लिए बहावा मात्र बन जायेंगे। अतः उच्चतम
 न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा संशोधित 31 (c) धारा को अर्थात् 42वें संशोधन को धारा 4 को
 अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है क्योंकि यह मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के
 समुचित को नष्ट करता है और नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए पवित्र किन्ने
 भी कानून को न्यायिक प्रणालीकरण को शक्ति से पूर्णतः बाहर रखती है भले ही वह अनुच्छेद 14
 और 19 में गारंटी दिये गये अधिकारों से असंगत हो क्यों न हो। न्यायालय का मत है कि
 अनुच्छेद 14 और 19 के बिना अर्थात् समानता और स्वतन्त्रता के अधिकार के बिना व्यवस्था
 प्रजातन्त्र का अस्तित्व सम्भव नहीं। अतः इनके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संक्षेप में, मूल
 अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में से किसी एक को प्राथमिकता देने को अपरिपक्वता की
 अनिवार्यता से तालमेल और समुचित बनाने रखने को अपरिपक्वता है। संविधान-निर्माताओं की
 यही मंशा थी और प्रजातन्त्र की भी यही मंशा है।

नीति निर्देशक तत्वों को मान्यता को प्रदान करने हुए संविधान अधिनियम ने अपने द्वारा एक
 द्विचरण प्रक्रिया प्रदान की है। आधे-आधे में प्रक्रिया में निम्नलिखित हैं। 1. भारतीय संविधान
 के अन्तर्गत मूल अधिकारों के प्राथमिकता प्रदान है। इसकी अधिकतम आवश्यकताएँ या तो
 संविधान में प्रदान की गई हैं। 2. भारतीय संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों को प्राथमिकता
 प्रदान करने के लिए आवश्यक

[illegible]

...को लाने के लिए कठिन परिश्रम किया गया है।
...को लाने के लिए कठिन परिश्रम किया गया है।
...को लाने के लिए कठिन परिश्रम किया गया है।
...को लाने के लिए कठिन परिश्रम किया गया है।

... का निर्माण किया गया है।
... के रूप में कार्य करता है। अनेक राज्यों में इसकी कक्षा तक
... की गई है। सातवां नियम द्वारा निरक्षरता का अर्थ
... करने की दिशा में गंभीर प्रयास किये हैं।
... का उल्लेख किया है। कुछ राज्यों में
... की गई है।

...के विकास के लिए अनेक साधन खोजे गये हैं, जिनके अन्तर्गत नये नये साधन भी आये हैं।

1956 का हिन्दू उत्तराधिकार नियम का विकास को और प्रभावित करना है।

सामाजिक विकास के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास
को तीन प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
(क) सामाजिक अथवा सांस्कृतिक अपराध है। समाज के अनुचित
प्रथाओं को दूर करने के लिए शिक्षण के माध्यम से अपराध नहीं
होना चाहिए।

— विभाग को दिनांक २६ मार्च १९७३ को प्रत्यक्ष स्थाने मिले हैं। अनेक कार्यक्रमों को भी इस दिनांक २६ मार्च १९७३ को प्रत्यक्ष स्थाने मिले हैं।

संयोजन अध्ययन का प्रत्येक निष्कर्ष

भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख या दस्तावेज है
(Indian Constitution - As a Social Document)

संविधान-संशोधन का यह प्रश्न कि, 'भाषाईय संविधान प्रस्ताव' एवं प्रस्ताव; इस संविधान-संशोधन की पूर्णता है। इनका मत है कि भाषाईय संविधान का अर्थव्यवस्थापरक प्रभाव है जो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रभावित करेगा, एवं कदाचित् ही इस उद्देश्य को पूर्णतः नष्ट कर देगा। इसका मत है कि भाषाईय संविधान का अर्थव्यवस्थापरक प्रभाव है जो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रभावित करेगा, एवं कदाचित् ही इस उद्देश्य को पूर्णतः नष्ट कर देगा। इसका मत है कि भाषाईय संविधान का अर्थव्यवस्थापरक प्रभाव है जो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रभावित करेगा, एवं कदाचित् ही इस उद्देश्य को पूर्णतः नष्ट कर देगा।

मूल अधिकार भारत में एक स्वतंत्र और समतावादी समाज की स्थापना करते हैं। व्यक्ति को एक निरंकुश एवं लोकतान्त्रिक राज्य के समान और प्राधिकृत से ही मुक्ति मिले। यद्यपि हम समाज, समूह, जाति, विचारों अथवा धर्म के प्रति अपने अधिकारों से भी मुक्ति दिलाने हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएँ हैं कि व्यक्ति को कार्य, धर्म, भाषा तथा कुछ को छोड़कर सभी मामलों में अधिकार हैं। हमारी सभी समता और स्वायत्ता का संरक्षण ही समाज के अस्तित्व की पुष्ट करता है। जिस विचारों पर आधारित मुक्त भारतीय समाज की स्थापना पहले की गई थी और जिसे सामाजिक संदर्भों और प्रत्यक्ष द्वारा बनाये रखा गया था, उसे समाज नियमानुसार करता है।

राज्य की नीति के दिशैका तत्व भारतीय जनता को उसके अधिकार से मुक्ति दिलाते हैं। ये संविधान को अंग्रेजों में सत्यता नाएकता के लिए प्रेरणादायक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये अर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं। ये लोकतन्त्रवादी-समाजवादी राज्य की नीति करते हैं। ये समाज में सार्वजनिक भावना जनता को उसकी दमनीय अवस्था से मुक्तता दिलाता करते हैं। ये इसे अपने व्यक्ति के विनाश के लिए अवसर देना करते हैं। ये उसके समीपवर्ती का प्रति में आने वाली भाषाओं को मुक्तता दिलाते हैं।

केरलानन्द भारती प्रथम केरल राज्य के विचार में न्यायाधीश हेनरी और मुख्य जे. भाग दीन और धार के सामाजिक उद्देश्यों को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है, "मूल अधिकारों का उद्देश्य एक समाजावादी समाज को बनाना है। इनका उद्देश्य सभी नागरिकों को सफल के दमन और प्रतिस्पर्धा से मुक्ति दिलाना है और सभी के निरूपे श्रवणता उपलब्ध करना है। निन्दितक शक्तों का उद्देश्य अतिरिक्त शक्ति से सामाजिक शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मुक्त सामाजिक और आर्थिक शक्तों को जोड़ना है। इन शक्तों का एक सामाजिक प्रयोग प्राप्त संविधान सामान्य व्यक्ति को मूल रूप से अभिव्यक्त करता है और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को नष्ट करने के लिए। इनका उद्देश्य भारतीय जनता को सफलतापूर्वक बनाने के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए है। इनका उद्देश्य भारतीय जनता को सफलतापूर्वक बनाने के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए है। इनका उद्देश्य भारतीय जनता को सफलतापूर्वक बनाने के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए है।

अनुच्छेद 26 सभी जातियों को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को स्थापित और चलाए जाने, अपने धर्म विधायक कार्यों को प्रबन्ध करने, जंगम और प्रत्येक सम्पत्ति के अर्जन एवं स्वाध्याय को और ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रसार करने का अधिकार देता है।

भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। राज्य किसी व्यक्ति को किसी अनुष्ठान धर्म के अपनाने में किसी धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहता। राज्य किसी व्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत में धर्म की व्यक्ति का निजी मामला समझा जाता है। राज्य धार्मिक मामलों में नहीं हस्तक्षेप करता है जब धर्म सामाजिक न्याय, न्यायिक या अन्तर्गत पदा करता है, अथवा धार्मिक संस्थाओं का कुप्रबन्धन करता है या धर्म राज्य की लोककल्याणकारी नीतियों अथवा धार्मिक व सामाजिक सुधारों के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करता है। इस तरह राज्य लोक व्यवस्था, न्याय और स्वतन्त्रता के धर्म में हस्तक्षेप करने को अपने आपको स्वतन्त्र कहता है।

अनुच्छेद 29 भारत के राज्य क्षेत्र का उसका किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के धर्म और भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यह धर्म, भाषा, लिपि व संस्कृति धर्मों के प्रकार के वर्गों को उपलब्ध है।

अनुच्छेद 29 (2) इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य द्वारा पोषित या स्थापित संस्थाएँ अपने किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल भाषा, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं कर सकती।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी भारतीय संविधान की व्यवस्थाएँ केवल अद्वितीय धर्मों के अल्पसंख्यक वर्गों को आश्वस्त करती हैं कि उनकी भाषा, लिपि व संस्कृति संरक्षण द्वारा सुरक्षित है और राज्य कानून द्वारा किसी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म, भाषा, लिपि व संस्कृति धोपने का प्रयास नहीं करेगा। भारत में नागरिकों को धर्म अन्तर्गत निरपेक्ष है, योग्यता रखने पर नागरिक किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश कर सकते हैं। राज्य केवल कुशल प्रबन्ध के लिए उनका धर्म बनाए रखता है। उपर्युक्त व्यवस्थाओं ने अल्पसंख्यकों में एक नये विश्वास की भावना उत्पन्न किया है तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित है।

अल्पसंख्यक वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध-भारत में कुछ वर्ग और जातियाँ अल्पसंख्यक हैं। इनमें पिछड़ी हुई या कमजोर हैं कि विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा उनके अधिकारों का रक्षण और विकास करना या राष्ट्र

- (i) अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ बनाने का अधिकार देता है।
- (ii) अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े हुए वर्गों को किन्हीं वर्ग के लिए, यदि राज्य को राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में उच्च पदों प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का अधिकार देता है। इस तरह यह अनुच्छेद राज्य को राज्य के अधीन सेवाओं में "संरक्षित क्षेत्र" का अधिकार देता है।
- (iii) अनुच्छेद 16 राज्य पर दायित्व करता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अन्य सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्त्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
- (iv) अनुच्छेद 275 राज्य को उन योजनाओं के लिए संघीय सहायता या अनुदान को व्यवस्था करता है जिनका उद्देश्य उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को उच्च स्तर के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करना है। यदि केवल यह है कि इस प्रकार की योजनाओं को राज्य में लेने से पहले राज्य भारत सरकार पर अनुमति प्राप्त कर ले।
- (v) अनुच्छेद 331 इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को राज्य में लोकसभा में अंग-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो प्रतिनिधियों को नामजद कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में अंग-भारतीय समुदाय का एक प्रतिनिधि नामजद कर सकता है।
- (vi) अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। इन जातियों के रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करने के लिए अनुच्छेद 338 में विशेष अधिकारी की और अनुच्छेद 340 में आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- (vii) अनुच्छेद 347, 350, 350 (क) और 350 (ख) में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा के संरक्षण, भाषा सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने, मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाएँ आदि देने से सम्बन्धित अनेक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

4. सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र-प्रोत्साहन डॉ. जे.वेल्ले ने कहा है कि "जकरतन्त्र (निर्धन) व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं होते।" अतः भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्य की दिष्टि के लिए नीति निर्देशक तत्वों को रचना करता है। अतः भारत में "आर्थिक स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र है।" निर्देशक तत्व "आर्थिक तानों के अन्तर्गत आते हैं।"

दमप्राप्त की सुविधाएँ प्रदान करेंगे। इस अनुच्छेद में प्राप्ति में सुविधाएँ बराबरी के विकास पर विशेष बल दिया गया है। अनुच्छेद 43 (क) उद्योगों के प्रचलन में कामगारों के भाग लेने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने पर बल देता है। यह अनुच्छेद राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह गरीबों और बंजरों तथा अन्य दुर्भाग्य और बाधक घटायों को मरुती के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके लाभ का प्रतिपेक्ष करने के लिए कदम उठाएगा।

इन व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य कृषि उद्योगों के विकास द्वारा गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है, गरीबों और गरीबों को असमानताओं को दूर करना है तथा राष्ट्र को प्रशुद्ध करने रखा करता है।

- (iv) अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को व्यवस्था करता है।

संक्षेप में, मूल अधिकारों से निर्दिष्ट दस्तों की उपर्युक्त व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान प्रथमः मूल अनुच्छेदः एक सामाजिक दस्तावेज (प्रलेख) है। ये व्यवस्थाएँ विच्छेद 64 बलों में सामान्य हित में समता-सुधार, परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की प्रमुख प्रेरक शक्ति एवं आधार रही हैं।